336

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

Matter under

वीडियों प्रदर्शन के साथ-साथ बीडियों लाइब्रेरियां ग्रचानक दर्जनों की संख्या में कुल गई हैं। ये लाइब्रेरियां दो सी रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में लेती हैं श्रीर पंद्रह रुपये प्रतिदिन की दर से बीडियों कैसेट तथा डेढ सौ रुपये प्रतिदिन की दर से वीडियो कैसेट रिकार्डर किराए पर देती हैं। इस ग्रवैद्य वीडियो व्यापार के कारए। केवल उ. प्र. सरकार को कम दस करोड़ र. वार्षिक की क्षति उठानी पड़ रही है किन्तु भनोरंजन कर विभाग इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरा सरकार से श्रन्रोध है कि ऐसी फिल्मे देखने ग्रीर दिखाने वालों तथा इस प्रकार के अबैध घंधों में लगे लोगों के खिलाफ तुरन्त कड़े कानून बना कर कार्यवाही की जाए।

(iv) Need For Setting Up Industries In Gorakhpur (Uttar Pradesh) To Remove Poverts From That Area.

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : ग्राप कै माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान मैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वांसगांव, गोरखपूर के पिछड़ेपन एवं गरीबी को दूर करने के लिए विशेष रूप से ग्रीद्योगीकरण की तरफ धाकिषत करना चाहता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष धाधरा, कुग्रानो, तरेना, गनगरी, राप्ती एवं गौरां नदियां से बाढ़ श्राया करती है श्रीर इस मयंकर बाढ़ से लाखों लोग बेधर हो जाते हैं भ्रीर रोजी रोटी के लिए दर दर मार खाते हैं एवं सूखा भी भयंकर रूप से प्रभावित करता रहता है। फलस्वरूप कृषि कम हो जाती है। इस कमी के कारण श्राबादी का भार कृषि पर श्रधिक हो जाने से ग्रधिकांश लोग भूलमरी के शिकार हो जाते हैं। इसी से प्रभावित हो कर प्रान्तीय

सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया है। लेकिन इस घोषणा के बाद भी राज्य सरकार ने इस विषय पर अभी तक इयान नहीं दिया है। इसी संदर्भ में गत वर्ष मैंने केन्द्रीय सरकार से भी निवेदन किया था कि इसे पिछड़ा क्षंत्र घोषित करके उद्योग लगाएं। लेकिन श्रमी तक केन्द्रीय सरकार ने भी इस पर घ्यान नहीं दिया। मौभाग्यवश इस क्षेत्र में श्रनेक प्रकार के कच्चे माल उपलब्ध हैं।

लेकिन ग्रभाग्यवश इस क्षेत्र में न तो सार्वजिनिक क्षेत्र में, न निजी क्षेत्र में, न सहकारी क्षेत्र में ग्रीर न संयुक्त क्षेत्र में कोई उद्योग लगाया गया है। धतः ग्रापके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निम्न निवेदन करना चाहता हूँ कि इस निर्वाचन क्षेत्र को पिछड़ा हुन्ना क्षेत्र घोषित किया जाए तथा उरुवा वड्हलगंज के बीच में सूती मिल, गनने की मिल, पांडेपुर में ऊनी मिल, चीरी-चौरामें चमड़े का कारखाना लग।या जाए, जिससे इस क्षेत्र का पिछड़ा-पन दूर हो सके।

(v) Need To Give More Time For Telugu Programmes Over The TV And AIR

*SHRI P. PENCHALAIAH (Tirupathi): Telugu is the largest spoken language in the country after Hindi. In addition to 6 crores of people living in Andhra Pradesh, there are a large number of Telugu people living in other parts of the country. But, unfortunately, this language is being neglected both on AIR and TV. Telugu programmes telecast on hook up during 15-8-82 to 31-3-83 were only of 30 minutes duration out of 365 hours. It is barely 0.1% whereas other regional languages got a major share. Telugu is a sweet language and known as the Italian of the East, the non-Telugu people do not find it difficult to understand. Moreover, Telugu happens to be the language in which the largest number of feature films were produced this year. Unlike the movies produced in other languages, Telugu movies are readily welcomed by family viewers throughout the country. There is no dearth in variety of programmes produced and presented in Telugu. Hence, it should not be difficult for Delhi and other Doordarshan Kendras and AIR to feature or broadcast them.

Hence I request the Hon. Minister of Information and Broadcasting to raise the time duration of Telugu programmes of National hookup on TV and to broadcast more Telugu programmes over AIR. Also I request for the allotment of more time for Telugu programmes over Delhi Doordarshan and other prominent Kendras.

(vi) Deterioration in the Working of Telephones in Patna (Bihar)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): There are 6 Telephone exchanges in Patna but the largest number of telephones i.e., 6,000 are in the telephone exchange which is situated in the premises of the General Post Office. The entire exchange was submerged in the devastating flood of 1975. It was required to change the entire exchange but it was partly repaired. The life of that exchange has expired. Therefore, it needs to be replaced at the earliest.

Out of 14,500 connections, 3,000 have already been declared as useless but no new lines have been provided in their place. 2,500 people are in the waiting list for a long time.

Today, most of the telephones in Patna remain out of order. When the telephones of V.I.Ps and Government officials remain out of order, then the situation regarding other people can only be imagined. The situation has deteriorated so much that even 197, 198, 199 and 180 etc are also not available.

About two years back, it was decided to instal an Electronic Exchange having a capacity of 8,000 telephones in Patna.

I urge the Communications Minister to bring about improvement in telephone system in Patna. He should make arrangements for installation of a new exchange in place of the present exchange which was installed in 1952-53, increase the capacity of telephones, make arrangements to provide connections to the persons in the waiting list, commission an electronic exchange having the capacity of 8,000 lines and instal new exchanges.

(vii) Admission of S.C. and S.T. Students in Jawaharlal Nehru University and Need for a Visitorial Enquing into its Working.

प्रो. ग्रजित कुमार मेहता (समस्ती-पुर): उपाध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना आदर्श विश्व-विद्यालय के रूप में हुई थी। इसकी विशिष्टता के बावजूद विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति में कुछ लोकतांत्रिक तत्व थे, जिनके कारए पिछड़े वर्गों ग्रीर क्षेत्रों के छात्रों का भी दाखिला इसमें संभव हो पाता या, जो कुछ लोगों को ग्रसह्य था। विदेव-विद्यालय अनुदान आयोग की अनुशन्सा के ग्राधार पर यहां के कुल तीन हजार छात्रों में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की संख्या 20 प्रतिशत यानी 600 होनी चाहिए थी, किन्तु है केवल 316/350 प्राध्यापकी में केवल चार ही ग्रनुसूचित जाति के हैं। सितम्बर 1982 में विश्वविद्यालय अनुदान भायोग की सिफारिशें लागू करने के ग्रिविकारियों के श्राश्वासन के बावजूद भी ग्रक्तूबर 1982 में प्राध्यापकों की मरती के विज्ञायन में आरक्षरण का प्रावधान नहीं किया गया।

इसी बीच शिक्षा के स्तर के नाम पर नामांकन के समय पिछड़े क्षेत्र के पिछड़े छात्र प्रवेशार्थियों को दी जाने वाली चार पायंट्स की सुविधा को वापस लिया जाना संकेत करता है कि उनकी नगण्य संस्था की